आसा नंद **बहुत।** हरीश कुमार और अन्य (जे. वी. गुप्ता, जे.

नैतिक आवश्यकता के प्रश्न पर विद्वान अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील, कानूनी रूप से कायम रह सकती है या नहीं। इस पहलू पर, फिर से, हमने विद्वान वकील को बहुत विस्तार से सुना था और पाया कि रिकॉर्ड पर पूरी सामग्री पर विचार करने पर, यह एक तथ्य के रूप में पाया गया था कि मकान मालकिन को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए परिसर की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता के वकील एम. गोयल रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर हमें राजी नहीं कर सके, विपरीत दृष्टिकोण अपनाना। विद्वान अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में दिए गए कारणबहुत वजनदार हैं और हमें इसकी पुष्टि करने में कोई संकोच नहीं है।

(10) किसी अन्य मुद्दे का आग्रह नहीं किया गया था।

(11) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, यह याचिका विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में, हम नहीं करते हैं। लागत के संबंध में आदेश। याचिकाकर्ता को परिसर खाली करने और मकान मालकिन को कब्जा सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है।

Surinder Singh, J.—I agree.

एन.के.एस.

जे. वी. गुप्ता से पहले जे.

एएसएसए एनएएनडी, - याचिकाएं।

बनाम

हरीश कुमार और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल संशोधन सं. 1982 का 968।

16 जुलाई, 1982।

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का वी) - धारा 35-बी, 115 (2) और आदेश *XX* नियम 6-ए - स्थगन की मांग करने के लिए वादी पर लगाए गए जुर्माने - स्थगित तिथि पर भुगतान नहीं की गई लागत और कार्यवाही जारी रखने की अनुमति - प्रतिवादी द्वारा उस तारीख के लंबे समय बाद मुकदमे को अस्वीकार करने के लिए आवेदन जिस तारीख को लागत का भुगतान करने की आवश्यकता थी - इस तरह के आवेदन - क्या सक्षम - क्या सक्षम - इस तरह के आवेदन की अनुमति देने और वाद को खारिज करने का आदेश - क्या धारा 115 के तहत संशोधन योग्य है - ऐसा आदेश - क्या किसी मामले3 के दायरे में आता है जिसका निर्णय लिया गया है।

माना जाता है कि एक आवेदन की अनुमति देने और लागत का भुगतान न करने के आधार पर मुकदमा खारिज करने का आदेश स्पष्ट रूप से गिर जाएगा

'किसी भी मामले पर फैसला हो चुका है' वाक्यांश के दायरे में और पारित किए गए डिक्री के बावजूद, इस तरह के आदेश में संशोधन सक्षमहोगा। इसके अलावा, 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 में जोड़े गए एक्सप्ला नेशन में प्रावधान है कि 'किसी भी मामले का जो फैसला किया गया है' अभिव्यक्ति में मुकदमा या अन्य कार्यवाही के दौरान किया गया कोई भी आदेश शामिलहोगा। इस तरह के आवेदन पर पारित आदेश एक मुकदमे के दौरान किया गया आदेश है और इसलिए, स्पष्ट रूप से इस अभिव्यक्ति के भीतर आता है। ऐसी स्थिति में, यह महत्वहीन हो जाता है कि इसके परिणामस्वरूप, मुकदमाट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(सेवा 5)।

यह माना गया कि संहिता की धारा 35-बी में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि निर्धारित किसी तारीख को मामले को लागत ों के भुगतान पर स्थगित कर दिया जाता है, तो ऐसी लागतों का भुगतान वादी द्वारा मुकदमे के आगे के अभियोजन के लिए एक शर्त होगी, जहां वादी को ऐसी लागतों का भुगतानकरने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि एक ऐसे मामले में जहां लगाए गए लागतों का भुगतान उसी तारीख को नहीं किया जाता है जब लागत का भुगतान किया जाना है, न्यायालय का ध्यानआकर्षित किया जाना चाहिए ताकि मुकदमे का आगे का अभियोजन केवल तभी हो सके जब आवश्यक अनुपालन किया गया हो। यदि संहिता की धारा 35-बी के प्रावधानों को लागू करने का इरादा रखने वाले पक्ष द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है और चुप रहता है और अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है, तो उसे उस तारीख के बाद कथित गैर-भुगतान, यदि कोई हो, को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में संहिता की धारा 35-बी के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं।

(सेवा 6)।

सी.पी.सी. की धारा 115 के तहत याचिकाश्री आर सी बंसल, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, करनाल के न्यायालय के दिनांक 24 मार्च, 1982 के आदेश में संशोधन के लिए वादी के वाद को खारिज कर दिया गया और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एम. आर. खन्ना ने यह बात कही।

श्री एस. के. गोयल, अधिवक्ता , प्रतिवादीहैं।

निर्णय

जे. वी. गुप्ता, जे.

1. यह 24 मार्च, 1982 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ है, जिसके तहत इसनेस्थगन के लिए लागत का भुगतान न करने के आधार पर मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रतिवादी-प्रतिवादियों की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। नतीजतन, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता ने वर्ष 1979 में प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया और प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा लागू की। पर

6 फरवरी, 1981 को वादी का कोई सबूत पेश नहीं किया गया और स्थगन का अनुरोध किया गया, जिसे30 रुपये की लागत के भुगतान के अधीन अनुमति दी गई। इसके बाद 26 मार्च, 1981 को वादी के साक्ष्य के लिए मामले की सुनवाई होनी थी। ट्रायल कोर्ट के 26 मार्च, 1981 के आदेश में लिखा है, -

> "वर्तमान: श्री एस. के. सहगल, वकील, वादी के वकील;
>
> श्री हरि किशन, प्रतिवादी (व्यक्तिगत रूप से)।
>
> वादी का कोई सबूत मौजूद नहीं है, प्राप्त समन वापस नहीं मिला। एक तिथि का अनुरोध किया जाता है। विरोध नहीं किया। 16 मई, 1981 को पी.एफ. अनुरोध के अनुसार समन का एक सेट दस्ती दिया जाए ।

मामला लंबित रहा और समय-समय पर विभिन्न तिथियां तय की गईं। 6 मार्च, 1982 को, यानी लगभग एक साल बाद, प्रतिवादियों ने 26 मार्च, 1981 को लागत का भुगतान न करने के आधार पर मुकदमा खारिज करने के लिए आवेदन दिया।

आसा नंद **बहुत।** हरीश कुमार और अन्य (जे. वी. गुप्ता, जे.

3. इस >1 आवेदन ों की सूचना वादी को दी गई थी, आईओ ने 9 मार्च, 1982 को उस पर अपना जवाब दाखिल किया। इसमें दलील दी गई थी कि छह फरवरी, 1981 को उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान प्रतिवादियों के वकील को 26 मार्च, 1981 को किया गया था, लेकिन असावधानी के कारण 26 मार्च, 1981 के अंतरिम आदेश में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि प्रतिवादियों के वकील को लागत का भुगतान किया गया था। इसमेंआगे कहा गया है कि यदि 6 फरवरी, 1981 को उन पर लगाए गए 30 रुपये के जुर्माने का भुगतान 26 मार्च, 1981 को प्रतिवादियों के वकील को नहीं किया गया होता, तो प्रतिवादी उन्हें सबूत पेश करने की अनुमति नहीं देते और लागत का भुगतान न करने के लिए अदालत के ध्यान में लाते। यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि इस बीच, वकील ने कहा कि वकील की मृत्यु हो गई थी। ट्रायल कोर्ट पक्षों के वकील ों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्थगन की लागत नहीं थीक्योंकि अगर इसका भुगतान किया गया होता, तो 26 मार्च, 1981 के आदेश में इसका उल्लेख किया गया होता। इस प्रकार, नागरिक प्रक्रिया संहिता (जिसे बाद में संहिता कहा जाता है) की धारा 35-बी के प्रावधानों और आनंद प्रकाश बनाम इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए । बीएचआरत भूषण राय और एक अन्य (1), प्रतिवादियों की ओर से दायर आवेदन स्वीकार कर लिया गया था। नतीजतन, वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। समापन

(1) ए.आई.आर. 1981 पंजाब और हरियाणा 269 (एफ.बी.),

आदेश के पैराग्राफ, संशोधनके तहत लिखा है, -

> "चूंकि स्थगन की लागत का भुगतान नहीं किया गया है और नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 35-बी को ध्यान में रखते हुए, जिसे हमारे अपने माननीय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ प्राधिकरण के साथ पढ़ा जाता है, प्रतिवादियों का आवेदन स्वीकार किया जा सकता है और इसलिए, इसलिए, बचाव पक्ष का आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। वादी का मुकदमा खारिज किया जा सकता है। इसलिए, मैं प्रतिवादियों के आवेदन को स्वीकार करता हूं। नतीजतन, वादी का मुकदमा भी खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, मामले की अजीब स्थिति को देखते हुए,पार्टियों को अपनी लागत ों को वहन करने की आवश्यकता है। फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया जाए।

उसी से व्यथित, वादी इस न्यायालय में संशोधन के लिए आया है।

4. प्रतिवादियों की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि पुनरीक्षण याचिका मान्य नहीं हैक्योंकि आक्षेपित आदेश एक अपील योग्य था और इस प्रकार, संहिता की धारा 115 की उप-धारा (2) के मद्देनजर, यह न्यायालय किसी भी डिक्री या आदेश को अलग-अलग या उलट नहीं करेगा, जिसके खिलाफ अपील इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, इसके अधीनस्थ। विद्वान वकील के अनुसार, ट्रायल कोर्ट का आक्षेपित आदेश संहिता के आदेश XX नियम 6-ए के प्रावधानों के मद्देनजर एक डिक्री के समान है और इसलिए याचिकाकर्ता का एकमात्र उपाय ट्रायल कोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर करना था। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने आत्मा राम बनाम आत्मा पर भरोसा किया । पंजाब वित्तीय निगम और अन्य (2). दूसरी ओर, याचिकाकर्ता आर के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि लागू आदेश एक समग्र है क्योंकि इसने याचिकाकर्ता की ओर से दायर आवेदन का निपटारा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप वादी का मुकदमा खारिज कर दिया गया था। वर्तमान पुनरीक्षण याचिका ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है , जिसमें वादी के मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रतिवादियों की ओर से दायर आवेदन को स्वीकार किया गया है और इसलिए, संहिता की धारा 115 की उप-धारा (2) के प्रावधान इस मामले में आकर्षित नहीं होते हैं। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने मेजर एस. एस. खन्ना बनाम मेजर एस. खन्ना पर भरोसा किया । एफ. जे. ढिल्लों (3), और सिरी कृष्ण भारद्वाज बनाम मनोहर लाल गुप्ता और अन्य, (4).

(2) 1968 पंजाब लॉ रिपोर्टर 167.
(3) ए.आई.आर. 1964 एस£. 497.
(4) ए.आई.आर. 1977 दिल्ली 226.

5. प्रारंभिक आपत्ति पर पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, मेरा सुविचारित मत है कि उक्त आपत्ति में कोई बल नहीं है। कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सिरी कृष्ण भरदवाएफएस मामले (सुप्रा) में यह माना गया है कि यदि लागू आदेश वह है जो वाक्यांश के दायरे में आता है 'किसी भी मामले पर फैसला किया गया है, तो इसे संशोधित किया जाएगा। आदेश XXXVII नियम 2 (2) (उस मामले में) के तहत एक आदेश प्रतिवादी को पेश होने के लिए अनुमति देने से इनकार करता है और आदेश XXXV के तहत मुकदमा दायर करता है। III को दूरगामी परिणाम वाला माना गया था जो स्पष्ट रूप से वाक्यांश 'किसी भी मामले पर निर्णय लिया गया है' के दायरे में आएगा क्योंकि जहां तक विवाद का संबंध था, विवाद वास्तव में समाप्त हो गया था। मैंपारित किए गए आदेश के अनुसार, इस तरह के आदेश के खिलाफ एक संशोधन को सक्षम माना गया था। इसके अतिरिक्त, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 104) के तहत संहिता की धारा 115 में जोड़े गए स्पष्टीकरण में यह प्रावधान है कि किसी भी मामले पर निर्णय लिया जा चुका है, जिसमें वाद या अन्य कार्यवाही के दौरान दिया गया कोई भी आदेश शामिल होगा। उसी के मद्देनजर, प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश, मुकदमे के दौरान किया गया एक आदेश है और इसलिए, स्पष्ट रूप से 'किसी भी मामले का फैसला किया गया है' अभिव्यक्ति के भीतर आता है। ऐसी स्थिति में, यह महत्वहीन हो जाता है कि इसके परिणामस्वरूप, वादी के मुकदमे को ट्रायल कोर्ट द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

6. अब पुनरीक्षण याचिका के गुण-दोष पर आते हुए, यह अजीब है कि 6 फरवरी, 1981 को वादी पर लगाए गए 30 रुपये के जुर्माने का कथित रूप से भुगतान न करने के कारण आवेदन लगभग एक साल बाद, यानी 6 मार्च, 1982 को दायर किया गया था। इतने लंबे समय के बाद दायर किया गया आवेदन अपने आप में खारिज होने के लायक है। केवल यह तथ्य कि 26 मार्च, 1981 के अंतरिम आदेश में लागत का भुगतान दर्ज नहीं किया गया था, अपने आप में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था किसरकार द्वारा किसानों को लागत का भुगतान नहीं किया गया था। बेशक, प्रतिवादियों के वकील, जिन्हें लागत का भुगतान करने का आरोप लगाया गया था, अब जीवित नहीं थे। इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरा सुविचारित विचार है कि संहिता की धारा 35-बी के प्रावधान बिल्कुल भी आकर्षित नहीं थे। संहिता की धारा 35-ख में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि यदि निर्धारित किसी तारीख को मामले को लागत ों के भुगतान पर स्थगित कर दिया जाता है, तो ऐसी लागतों का भुगतान वादी द्वारा वाद के आगे के अभियोजन के लिए एक शर्त होगी,जहां सादे झगड़े कोऐसी लागतों का भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इस प्रकार, यह उचित होगा निष्कर्ष यह है कि ऐसे मामले में जहां लगाए गए लागतों का भुगतान नहीं किया जाता है, उसी तारीख को जब लागत का भुगतान किया जाना है, अदालत का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए ताकि मुकदमे का आगे अभियोजन केवल तभी हो सके जब आवश्यक अनुपालन किया गया हो। यदि संहिता की धारा 35-बी के प्रावधानों को लागू करने का इरादा रखने वाले पक्ष द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है, और चुप रहता है और अदालत को मुकदमे के साथ सहमति देने की अनुमति देता है, तो उसे उस तारीख के बाद कथित गैर-भुगतान, यदि कोई हो, को आंदोलन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में,संहिता की धारा 35-बी के समर्थक बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। इस संबंध में ट्रायल कोर्ट का पूरा दृष्टिकोण गलत और अवैध है क्योंकि इसने अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से और भौतिक अनियमितता के साथ कार्य किया है। आनंद प्रकाश के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले की ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत व्याख्या की गई है। इसके अलावा उस मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा

गयाहै कि यदि पार्टी लागत लगाने के आदेश की तारीख के बाद निर्धारित तारीख पर लागत का भुगतान करने में विफल रहती है, तो अदालत के लिए मुकदमे के अभियोजन को अस्वीकार करना अनिवार्य है। इसका अर्थ है, जैसा कि पहले कहा गया है, कि अगली तारीख को जब लागत का भुगतान किया जाना है, तो संहिता की धारा 35-बी के तहत आवश्यक आदेश, यदि कोई हो, ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

7. जैसा कि आईवीउपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, यह संशोधन सफल होता है और इसकी अनुमति दी जाती है। लागू किए गए आदेश कोलागत के साथ अलग रखा गया है। लागत 200 रुपये आंकी गई है। पक्षकारों को उनके वकील के माध्यम से 10 अगस्त, 1982 को निचली अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। ट्रायल कोर्ट कानून के अनुसार मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगा। मामले के रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजे जाएं।

एन. के. एस.

एम. एम. पुंछी से पहले, जे।

जागीर सिंह, - याचिकाकर्ता,

बनाम

ग्राम पंचायत, ग्राम रायपुर कलां और
अन्य, उत्तरदाता।

आपराधिक संशोधन सं. 1980 का 674।

22 जुलाई, 1982।

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का II) – धारा 345
पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV) – धारा *19* – ग्राम

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा